

उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय,
अल्मोड़ा

प्राथमिकताएँ एवं योजनाएँ

शेखर विश्वविद्यालय की प्राथमिकता यह है कि उत्तराखण्ड राज्य के सामाजिक सरोकारों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कौशल एवं उद्यमिता विकास के पाठ्यक्रम चलाये जाएँ। वर्तमान में मूलभूत संसाधनों के अभाव में सभी पाठ्यक्रमों को पी0 पी0 पी0 मोड में चलाए जाने की योजना है।

हला पाठ्यक्रम **ISOL** फ़ाउंडेशन के सहयोग से निम्नलिखित दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाये जायेंगे-

1. पोषण, स्वास्थ्य एवं कल्याण (Nutrition, Health and wellness)

2. सामाजिक उद्यम एवं दीर्घकालीन जीवनयापन (Social Enterprise and Sustainable Development)

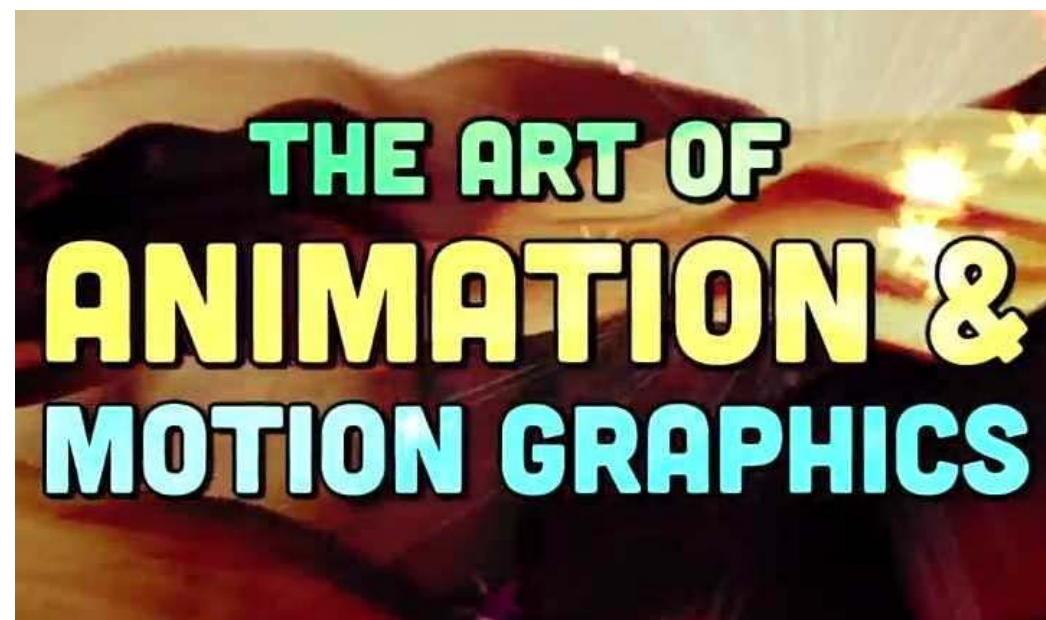
ये दोनों पाठ्यक्रम न केवल राज्य के युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने में सहायक होंगे, अपितु उत्तराखण्ड की खान-पान एवं स्वास्थ्य से संबन्धित पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़कर उन्हें बेहतर बाजार में उपलब्ध करवाने के साथ-साथ कुपोषण जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाने में सहायक होंगे।



IL&FS के सहयोग से आतिथ्य प्रबंधन एवं खदरा प्रबंधन के दो पाठ्यक्रम चलाये जाने की प्रीक्रिया चल रही है,जिनका इंडस्ट्री से इस प्रकार सोमंजस्य किया जाएगा कि अध्धयन के दौरान विध्यार्थियों को **Paid internship** मिले एवं पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर उन्हें रोजगार की गारंटी हो ।



राखंड की लोक - संस्कृति, कला, संगीत व सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित कर
को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने के लिए ग्राफिक्स, एनिमेशन,
गेरमिंग आर्ट, फोटोग्राफी, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, मीडिया आदि माध्यमों का समावेश
पीजी डिप्लोमा प्रारम्भ करने की योजना है जिसके लिए NIFT जोधपुर अकादेमिक
योग करने को तैयार है। यह पाठ्यक्रम स्व-वित्त श्रेणी के अंतर्गत चलाया जाना है
जिन मूलभूत संसाधनों हेतु सरकार से अनुरोध किया जा रहा है ।



श्रेणी के अंतर्गत ही राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों एवं उपलब्ध
को ध्यान में रखकर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को
करने की योजना है-

**Internet of Things
Cloud Computing
Information Security
Digital Marketing and Advertisement**

संस्थान की स्थापना हेतु यदि राज्य सरकार से समचित धनराशि प्रदान हो सके
तो सत्र से इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किया जा सकता है ।
संस्थानों द्वारा सेन्सरों के माध्यम से तापक्रम, CO₂ व CO स्तरों की जांच
संस्थानों की आगे के बारे में सूचना प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त आपदा,
जल वितरण, पर्यावरण अनुश्रवण, पर्वतीय कृषि, शिक्षा व स्मार्ट शहरों के क्षेत्र
संस्थानों का अनुप्रयोग हो सकता है । डिजिटल क्रांति के इस युग में क्रमांक
4 पर उल्लिखित पाठ्यक्रमों की महत्ता स्वतः सिद्ध है ।

खंड के प्राकृतिक उत्पाद, जड़ी-बूटियों एवं औषधियों के बारे में उपलब्ध
क ज्ञान को अत्याधुनिक वैज्ञानिक कसौटियों से प्रमाणित एवं परिमार्जित
के लिए निम्नलिखित दो स्कूलों

School of Natural Resources and Traditional knowledge systems

School of Biomedical Sciences

पना का प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसके लिए
कों, सहायक प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद स्वीकृत हुए थे लेकिन
मतता प्राप्त न होने से पदों को अभी तक विज्ञापित नहीं किया जा सका

तराखंड में उपलब्ध जड़ी-बूटियों पर आधारित दवाइयों द्वारा मरीजों को
करने के काफी तरीके पारंपरिक ज्ञान श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध हैं और यदि
न्याधुनिक वैज्ञानिक विधियों द्वारा विधिमान्य करा जा सके तो राज्य की
ग पहचान स्थापित की जा सकती है। इसके लिए पारंपरिक ज्ञान के
को **Reverse Pharmacology** तकनीक से प्रमाणित करना इस
द्वारा की योजना है।

उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों, इसका देश में स्थित विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं व संस्थानों से सामंजस्य स्थापित करने एवं इंडस्ट्री के लोगों को जोड़ने के लिए अल्मोड़ा में अप्रैल 16-17, 2017 को एक विचारावेश सत्र का आयोजन किया गया था। इसकी प्रमुख संस्तुतियों निम्नवत हैं-

1. **Hospitality, Retail, Arts and design** व **Computers** से संबन्धित पाठ्यक्रमों को स्व-वित्त श्रेणी के अंतर्गत प्रारम्भ किया जाए।
2. **School of Natural Sciences** के अंतर्गत **Plant Sciences** व **Phytochemistry** तथा **School of Natural Sciences** के अंतर्गत **Biotechnology** एवं **Pharmaceutical Sciences** के पाठ्यक्रम चलाये जाएँ।
3. शोध कार्यक्रमों को चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों की मांग की जाए। प्रयोगशालाएँ स्थापित हो जाने पर देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान एवं फ़ार्मा कम्पनियाँ **MOU** करने को तैयार रहेंगी।

भारत सरकार के Priority Programmes पर कार्यवाही एवं लंबित प्रस्तावों का विवरण एवं समाधान

1. ICT का उच्च शिक्षा में उपयोग- सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में मुफ्त WI-FI सुविधा उपलब्ध करवाकर भारत सरकार के SWAYAM प्रोग्राम का लाभ उठाना जो शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों को प्राप्त करने में सहायक होगा | WI-FI सुविधा होने पर उच्चशिक्षा संस्थान MOOCS, OER व विभिन्न देश व विदेश के विश्वविद्यालयों की पाठ्य सामग्रियों का भी उपयोग कर पाएंगे | प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के कार्यान्वयन में भी इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है |
2. स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अपने आस पास के परिवेश व पानी के स्रोतों की सफाई कर उनको पुनर्जीवित करने में योगदान दे सकता है |